+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(25 March 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- भारत द्वारा चीनी उत्पादों पर 'एंटी-डंपिंग' शुल्क लगाने की हालिया कार्यवाही
- भारत की वित्तीय प्रणाली लचीली और विविधतापूर्ण है: IMF रिपोर्ट
- भारतीय शहरों की विभिन्न हीट एक्शन प्लान (HAP) में क्या कमी है?
- MCQ

भारत द्वारा चीनी उत्पादों पर 'एंटी-डंपिंग' शुल्क लगाने की हालिया कार्यवाही:

मुद्दा क्या है?

- भारत ने घरेलू खिलाड़ियों को चीन से सस्ते आयात से बचाने के लिए इस महीने के दौरान वैक्यूम फ्लास्क और एल्युमिनियम फॉयल सहित पांच चीनी वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है।
- उल्लेखनीय है कि ये शुल्क इसलिए लगाए गए क्योंकि ये उत्पाद सामान्य से कम कीमत पर चीन से भारत को निर्यात किए जा रहे थे, व डंप किए जा रहे थे। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा इसके लिए सिफारिशें किए जाने के बाद ये शुल्क लगाए गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने पहले भी चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयात व डंपिंग से निपटने के लिए कई उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर बार-बार गंभीर चिंता जताई है, जो 2023-24 में 85 अरब डॉलर था।

डंपिंग क्या है और क्या यह कानूनी है?

- WTO के अनुसार डंपिंग, सामान्य रूप से, अंतरराष्ट्रीय मूल्य भेदभाव की स्थिति है, जहां आयात करने वाले देश में बेचे जाने वाले उत्पाद की कीमत निर्यात करने वाले देश के बाजार में उस उत्पाद की कीमत से कम होती है। सबसे सरल मामलों में, कोई व्यक्ति दो बाजारों में कीमतों की तुलना करके डंपिंग की पहचान कर सकता है। हालांकि, स्थिति शायद ही कभी, अगर कभी भी, इतनी सरल होती है।
- उल्लेखनीय है कि WTO नियमों के तहत डंपिंग तब तक वैध है जब तक कि विदेशी देश विश्वसनीय रूप से यह नहीं दिखा सकता कि निर्यातक फर्म ने उसके घरेलू उत्पादकों पर क्या नकारात्मक प्रभाव डाला है। डंपिंग तब भी निषिद्ध है जब यह घरेलू बाजार में किसी उद्योग की स्थापना में "भौतिक मंदता" का कारण बनता है।
- डंपिंग का मुकाबला करने और अपने घरेलू उद्योगों को शिकारी मूल्य निर्धारण से बचाने के लिए, अधिकांश देश टैरिफ और कोटा का उपयोग करते हैं।

डंपिंग इतनी विवादास्पद क्यों है?

- जैसे-जैसे मुक्त व्यापार और व्यापार बाधाओं को कम करने की अवधारणा दुनिया भर में प्रचलित हो रही हैं, डंपिंग को एक अनुचित व्यवहार के रूप में देखा जा रहा है जो ऐसी आर्थिक प्रणालियों का अनुचित लाभ उठाता है।

- विशेष रूप से, चीन जैसे विनिर्माण दिग्गजों पर सस्ते श्रम लागत, सरकारी सब्सिडी और घरेलू निर्माताओं को दिए जाने वाले अन्य लाभों की मदद से अपने माल की कीमत को अस्थिर स्तर तक कम करने का आरोप लगाया गया है।
- 2018 में, यूरोपीय संसद ने कहा, "यूरोपीय कंपनियों के लिए इससे प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल है और सबसे खराब स्थिति में फर्म बंद हो सकती हैं और कर्मचारी अपनी नौकरी खो सकते हैं"।

डंपिंग को रोकने की क्या प्रणाली उपलब्ध है?

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत, किसी देश के पास डंपिंग के प्रभावों को संतुलित करने के लिए एंटी-डंपिंग प्रतिवाद लागू करने का विकल्प होता है। ऐसा करने के लिए, आयात करने वाले देश के जांच अधिकारियों को डंपिंग के कारण हुई "क्षति" का निर्धारण करना होगा। इसमें घरेलू उद्योग को होने वाली 'भौतिक क्षति' या इसकी आशंका, या घरेलू उद्योग की स्थापना में 'भौतिक मंदता' शामिल है।
- एंटी डंपिंग उपायों के तहत देश डंपिंग के मार्जिन तक शुल्क लगा सकते हैं, जो सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच का अंतर है।

भारत द्वारा अपनायी गयी डंपिंग रोधी प्रणाली:

- भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत के व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) के द्वारा डंप किए गए आयातों के वॉल्यूम प्रभाव और मूल्य प्रभाव के संदर्भ में "क्षति" का विश्लेषण किया जा सकता है।
- भारतीय कानून यह भी प्रावधान करता है कि अनुशंसित/लगाया जाने वाला एंटी-डंपिंग शुल्क डंपिंग मार्जिन से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग शुल्क माल के आयात पर लगने वाले सामान्य सीमा शुल्क के अतिरिक्त लगाया जाता है। और यदि संबंधित निर्यातक डंपिंग को हटाने के लिए अपनी कीमत को संशोधित करने का वचन देता है, तो देश के राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद जांच को समाप्त या निलंबित करने का उपाय भी है।
- उल्लेखनीय है भारत में, वाणिज्य विभाग एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश करता है, जबकि वित्त मंत्रालय इसे लगाता है।

भारत की वित्तीय प्रणाली लचीली और विविधतापूर्ण है: IMF रिपोर्ट

परिचय:

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वित्तीय प्रणाली तेजी से लचीली और विविधतापूर्ण हो गई है, जो तेज आर्थिक विकास से प्रेरित है और महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 मार्च को जारी एक विज्ञप्ति में मूल्यांकन के उच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों को स्वीकार करते हुए IMF के मूल्यांकन का स्वागत किया।

'भारत वित्तीय क्षेत्र स्थिरता आकलन' रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट 'वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम (FSAP)' का हिस्सा है, जो IMF और विश्व बैंक (WB) के बीच एक संयुक्त पहल है, जो किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का गहन विश्लेषण प्रदान करती है।
- 2024 में किए गए आकलन के आधार पर नवीनतम 'भारत वित्तीय क्षेत्र स्थिरता आकलन (India-FSSA)' रिपोर्ट, वित्तीय प्रणाली में सकारात्मक विकास पर प्रकाश

डालती है, जबकि विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र आकलन (FSA) रिपोर्ट अभी प्रकाशित होनी है।

FSSA रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- IMF की इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 2017 में पिछले FSAP आकलन के बाद से भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक लचीली और विविधतापूर्ण बन गई है। इस प्रणाली ने 2010 के दशक के संकटपूर्ण प्रकरणों से उबरते हुए महामारी के दौरान भी लचीलापन दिखाया है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFI) की वृद्धि और बाजार वित्तपोषण में वृद्धि ने वित्तीय प्रणाली को और अधिक विविधतापूर्ण और परस्पर जोड़ा है। इन परिवर्तनों के बावजूद, राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनी हुई है।
- IMF द्वारा किए गए तनाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि प्राथमिक ऋण देने वाले क्षेत्र आम तौर पर समष्टि-वित्तीय झटकों के प्रति लचीले हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी कमजोरी दिखाई देती है।
- उल्लेखनीय है कि बैंक और NBFC गंभीर समष्टि-वित्तीय परिदृश्यों में भी मध्यम ऋण देने के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं। हालांकि, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के

बैंकों (PSB) को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऋण जारी रखने के लिए अपने पूंजी आधार को मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है।

- रिपोर्ट में कुछ गैर-प्रणालीगत NBFC और शहरी सहकारी बैंकों (UCB) में कमजोरियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें आधारभूत स्थितियों के तहत भी नकारात्मक या न्यूनतम से कम पूंजी स्तर है। सकारात्मक बात यह है कि अल्पकालिक तरलता तनाव की कमजोरी काफी हद तक नियंत्रित है।

भारत के वित्तीय तंत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण की स्थिति:

- विनियमन और पर्यवेक्षण के मोर्चे पर, IMF ने NBFC के लिए विवेकपूर्ण आवश्यकताओं, विशेष रूप से पैमाने-आधारित नियामक ढांचे के लिए भारत के व्यवस्थित दृष्टिकोण की प्रशंसा की। IMF ने बड़ी NBFC के लिए बैंक जैसी तरलता कवरेज अनुपात (LCR) की शुरुआत की भी सराहना की।
- इस रिपोर्ट में प्रतिभूति बाजारों के लिए भारत के नियामक ढांचे में उल्लेखनीय सुधारों पर प्रकाश डाला गया, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेखित किया गया। कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि (CDMDF) की स्थापना जैसी प्रमुख पहलों को बाजार स्थिरता बढ़ाने के लिए स्वीकार किया गया।

- भारत के बीमा क्षेत्र को भी मजबूत और बढ़ते हुए के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें जीवन और सामान्य बीमा दोनों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इस क्षेत्र की स्थिरता का श्रेय बेहतर विनियमन और डिजिटल नवाचारों को दिया जाता है।

वित्तीय तंत्र में साइबर सुरक्षा की स्थिति:

- साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, IMF ने बैंकों, वित्तीय बाजार अवसंरचना (FMI), महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों और प्रतिभूति बाजार में अन्य प्रासंगिक खिलाड़ियों के लिए मौजूद रूपरेखाओं का मूल्यांकन किया।
- यद्यपि इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा जोखिम निगरानी में प्रगति की है, विशेष रूप से बैंकों के लिए, इसने लचीलेपन को और बढ़ाने के लिए क्रॉस-सेक्टरल और मार्केट-वाइड घटनाओं को कवर करने के लिए साइबर सुरक्षा संकट सिमुलेशन और तनाव परीक्षणों का विस्तार करने की सिफारिश की।

भारत के FSAP के मामले में सिफारिशें:

- भारत के FSAP के मामले में सिफारिशें मुख्य रूप से वित्तीय प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली में और सुधार लाने पर केंद्रित हैं तथा कई विस्तृत सिफारिशें संबंधित प्राधिकरणों/नियामकों की अपनी विकास योजनाओं के अनुरूप हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम (FSAP):

- वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम (FSAP) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का एक संयुक्त कार्यक्रम है। एशियाई वित्तीय संकट के मद्देनजर 1999 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र के संकटों की संभावना और गंभीरता को कम करने में देशों की मदद करने के लिए बैंक और फंड की विशेषज्ञता को एक साथ लाता है।
- FSAP एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है जिसके माध्यम से भाग लेने वाले देशों में मूल्यांकनकर्ता और अधिकारी वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं और उचित नीतिगत प्रतिक्रियाएँ विकसित कर सकते हैं।
- FSAP किसी देश के वित्तीय क्षेत्र को देखते समय ***तीन-आयामी दृष्टिकोण*** का पालन करता है:

  1. वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता बनाम इसकी कमजोरियाँ और जोखिम जो वित्तीय क्षेत्र के संकटों की संभावना या संभावित गंभीरता को बढ़ाते हैं।
  2. बुनियादी ढांचे, संस्थानों और बाजारों के संदर्भ में देश की विकासात्मक ज़रूरतें।
  3. चुने हुए वित्तीय क्षेत्र के मानकों और कोडों के पालन के साथ देश का अनुपालन।

भारतीय शहरों की विभिन्न हीट एक्शन प्लान (HAP) में क्या कमी है?

मामला क्या है?

- एक नए अध्ययन में पाया गया है कि कई भारतीय शहरों द्वारा प्रस्तुत की गई अधिकांश 'हीट एक्शन प्लान (HAP)' में देश में अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का अभाव है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी रणनीतियों वाले शहरों ने उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया।
- इस विश्लेषण में कहा गया है कि नियोजन में इस तरह के अंतराल के परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में अधिक लगातार, तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली 'हीट वेव' के कारण गर्मी से संबंधित मौतों की संख्या अधिक हो सकती है।

अध्ययन रिपोर्ट के बारे में:

- 'क्या भारत एक गर्म होती दुनिया के लिए तैयार है? भारत के कुछ सबसे अधिक जोखिम वाले शहरों में 11% शहरी आबादी के लिए गर्मी प्रतिरोध उपायों को कैसे

लागू किया जा रहा है' नामक अध्ययन नई दिल्ली स्थित शोध संगठन सस्टेनेबल फ्यूचर कोलैबोरेटिव (SFC) द्वारा किया गया था। इसे SFC, किंग्स कॉलेज लंदन (इंग्लैंड), हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (USA), प्रिंसटन यूनिवर्सिटी (USA) और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (USA) के शोधकर्ताओं ने लिखा था।

- अपने विश्लेषण के लिए, शोधकर्ताओं ने 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की पहचान की, जिनमें "खतरनाक ताप सूचकांक मूल्य में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद थी। ये शहर बेंगलुरु, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर, कोटा, लुधियाना, मेरठ, मुंबई और सूरत थे।

इस अध्ययन में भारतीय शहरों की HAP को लेकर क्या पाया गया?

- इस अध्ययन में पाया गया कि यद्यपि सभी नौ शहरों में अल्पकालिक आपातकालीन उपाय थे, जैसे कि पीने के पानी तक पहुँच और काम के शेड्यूल में बदलाव, लेकिन दीर्घकालिक कार्य या तो पूरी तरह से अनुपस्थित थे या खराब तरीके से लागू थे।
- उल्लेखनीय है कि इस अध्ययन में कहा गया है कि "सबसे अधिक गर्मी के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए घरेलू या व्यावसायिक शीतलन उपलब्ध कराना, खोए हुए काम के लिए बीमा कवर विकसित करना, 'हीट वेव' के लिए अग्नि प्रबंधन

सेवाओं का विस्तार करना और ट्रांसमिशन विश्वसनीयता और वितरण सुरक्षा में सुधार के लिए बिजली ग्रिड रेट्रोफिट्स" जैसे दीर्घकालिक उपाय सभी शहरों में अनुपस्थित थे।

- इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि लागू की जा रही दीर्घकालिक रणनीतियाँ मुख्य रूप से स्वास्थ्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करती हैं, न कि रोकथाम पर। अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दीर्घकालिक कार्यों को लागू करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी।
- महत्वपूर्ण रूप से, विश्लेषण में पाया गया कि संस्थागत बाधाएँ दीर्घकालिक कार्रवाई की संभावनाओं को सीमित करती हैं। अध्ययन में कहा गया है, "उत्तरदाताओं द्वारा पहचानी गई शीर्ष समस्या, नगर पालिका, जिला और राज्य सरकार के विभागों के भीतर और उनके बीच सरकारी विभागों के बीच स्थानीय समन्वय थी"।

हीट एक्शन प्लान (HAP) क्या होता है?

- हीट एक्शन प्लान (HAP) अनिवार्य रूप से अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और तैयारी योजना है।

- यह योजना संवेदनशील आबादी पर अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी, सूचना-साझाकरण और प्रतिक्रिया समन्वय को बढ़ाने के लिए तत्काल और साथ ही दीर्घकालिक कार्रवाई प्रस्तुत करती है।
- जुलाई 2024 में पूछे गए लोकसभा प्रश्न के उत्तर में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) राज्य अधिकारियों के सहयोग से हीटवेव की स्थिति वाले 23 राज्यों में HAP को लागू कर रहा है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQ

1. भारत द्वारा चीनी उत्पादों पर हाल ही में 'एंटी-डंपिंग' शुल्क लगाने की कार्यवाही की गयी है। भारत द्वारा अपनाई जाने वाली 'एंटी-डंपिंग' प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. भारत के व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा डंप किए गए आयातों के संदर्भ में "क्षति" का विश्लेषण किया जाता है।
   2. व्यापार उपचार महानिदेशालय के इस विश्लेषण के उपरांत उसके सिफारिश पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एंटी-डंपिंग' शुल्क लगाया जाता है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(a)

2. चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 'भारत वित्तीय क्षेत्र स्थिरता आकलन' रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) यह रिपोर्ट 'वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम' का हिस्सा है।

(b) यह रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली में सकारात्मक विकास पर प्रकाश डालती है।

(c) भारतीय वित्तीय प्रणाली ने 2010 के दशक के संकटपूर्ण प्रकरणों से उबरते हुए महामारी के दौरान भी लचीलापन दिखाया है।

(d) उपर्युक्त सभी सही कथन हैं।

Ans:(d)

3. चर्चा में रहे 'वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह वित्तीय क्षेत्र के संकटों की संभावना और गंभीरता को कम करने में विभिन्न देशों की मदद करने के लिए विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है।

2. इसकी शुरुआत एशियाई वित्तीय संकट के मद्देनजर 1999 में हुई थी।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(b)

4. विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत, किसी देश द्वारा डंपिंग के प्रभावों को संतुलित करने के लिए कितना एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जा सकता है?

(a) निर्यात की गयी वस्तु के मूल्य के बराबर

(b) निर्यात की गयी वस्तु डंपिंग मार्जिन का दोगुना

(c) निर्यातक देश में उस वस्तु की मूल्य के बराबर

(d) निर्यात की गयी वस्तु डंपिंग मार्जिन से अधिक नहीं

Ans:(d)

5. चर्चा में रहे 'हीट एक्शन प्लान (HAP)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और तैयारी योजना है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

2. यह योजना संवेदनशील आबादी पर अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया समन्वय को बढ़ाने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक दोनों कार्रवाई प्रस्तुत करती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)